

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

तीसरी तिमाही
वित्तीय वर्ष 2013

परिणाम सम्मेलन कॉल
जनवरी 31, 2013

मुख्य वक्ता : श्री आर० नागराजन
निदेशक (वित्त),
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

मर्यादक : श्री करण ओबराय, विश्लेषक,
जे०एम० फाइनेंशियल

मर्यादक देवियों एवं सज्जनों, नमस्कार। जे0एम0फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूटशनल सिक्वोरिटीज प्राइवेट लिमिटेड की मेजबानी में आयोजित पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय वर्ष 2013 के परिणाम सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपको स्मरण कराना चाहूँगा कि इस सम्मेलन के दौरान सभी प्रतिभागियों की लाइन्स सिर्फ लिसनिंग मोड में रहेगी और आपको आज के इस प्रस्तुतीकरण के उपरांत अपने प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाएगा। यदि इस सम्मेलन के दौरान आपको किसी प्रकार की सहायता की जरूरत हों, तो आप अपने टचटोन टेलीफोन पर * व उसके बाद 0 दबाकर आपरेटर को संकेत दे सकते हैं। कृपया ध्यान रखें कि इस सम्मेलन को रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब मैं इस सम्मेलन को जे0एम0 फाइनेंशियल से पधारे श्री करण ओबराय को सौंपना चाहूँगा। महोदय कृपया आप इस सम्मेलन का संचालन करें। धन्यवाद।

करण ओबराय धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार और पावर फाइनेंस द्वारा वर्ष 2013 की तीसरी तिमाही के परिणामों पर चर्चा में आपका स्वागत है। परिणामों पर चर्चा के लिए, श्री आर0 नागराजन, निदेशक (वित्त), हमारे बीच उपलब्ध हैं। मैं श्री आर0 नागराजन से अनुरोध करता हूँ कि वे हमें वित्तीय उपलब्धियों से अवगत कराएँ व इसके उपरांत हम प्रश्नोत्तर सत्र का मंच प्रारम्भ करेंगे। महोदय, मंच आपको सौंपता हूँ। धन्यवाद।

आर0 नागराजन नमस्कार। मैं श्री ओबराय को धन्यवाद देता हूँ कि आपने पीएफसी को निवेशकों तथा विश्लेषकों के साथ सम्मेलन कॉल आयोजित करने का यह अवसर दिया। यह सम्मेलन कॉल पिछली तिमाही सितम्बर 12 के लिए आयोजित सम्मेलन कॉल के पैटर्न पर ही आयोजित की जा रही है, जिसमें पहले वित्त, फिर उसके बाद पीएफसी में अन्य विकास/डेवलपमेंट व सेक्टरल डेवलपमेंट तथा पीएफसी में इनकी विवक्षा/इम्प्लीकेशन को रखा गया है। जैसे ही यह समाप्त होगा, हम आपके प्रश्नों को स्वीकार कर सकेंगे।

वित्तीय वर्ष 2012 व वित्तीय वर्ष 2013 के नौ माहों की तुलना में स्वीकृतियाँ 45 प्रतिशत बढ़कर रुपए 40,958 करोड़ से बढ़कर रुपए 59,574 करोड़ रही हैं। संवितरण/भुगतान 25 प्रतिशत बढ़कर रुपए 24,126 करोड़ से बढ़कर रुपए 30,175 करोड़ रहे हैं। ऋण सम्पत्ति 26 प्रतिशत बढ़कर रुपए 1,17,995 करोड़ से बढ़कर रुपए 1,48,282 करोड़ हुई है। आर-एपीडीआरपी के अलावा बकाया स्वीकृतियाँ दिनांक 31 दिसम्बर 2012 को रुपए 1,69,538 करोड़ हैं।

जहां तक मुनाफे का संबंध है, पीएटी 41 प्रतिशत बढ़कर रुपए 2,213 करोड़ से बढ़कर रुपए 3,125 करोड़ है। तुलनात्मक पीएटी 44 प्रतिशत बढ़कर रुपए 2,328 करोड़ से बढ़कर रुपए 3,355 करोड़ है। कुल आय 35 प्रतिशत बढ़कर

रुपए 9,353 करोड़ से बढ़कर रुपए 12,602 करोड़ है। शुद्ध ब्याज आय (एनआईए) 44 प्रतिशत बढ़कर रुपए 3,166 करोड़ से बढ़कर रुपए 4,546 करोड़ है। स्प्रेड 60 बीपीएस बढ़कर 2.22 प्रतिशत से बढ़कर 2.82 प्रतिशत है। एन.आई.एम. 47 बीपीएस बढ़कर 3.89 प्रतिशत से बढ़कर 4.36 प्रतिशत है।

वित्तीय वर्ष 2012 व वित्तीय वर्ष 2013 की तीसरी तिमाहियों की तुलना में स्वीकृतियाँ 45 प्रतिशत बढ़कर, रुपए 12,475 करोड़ से बढ़कर रुपए 18,444 करोड़ रही हैं। संवितरण/भुगतान 28 प्रतिशत बढ़कर रुपए 9,892 करोड़ से बढ़कर रुपए 12,621 करोड़ रहे हैं। पीएटी 1 प्रतिशत बढ़कर रुपए 1,108 करोड़ से बढ़कर रुपए 1,117 करोड़ है। तुलनात्मक पीएटी 57 प्रतिशत बढ़कर रुपए 791 करोड़ से बढ़कर रुपए 1,243 करोड़ है। आय 36 प्रतिशत बढ़कर रुपए 3,284 करोड़ से बढ़कर रुपए 4,466 करोड़ है। शुद्ध ब्याज आय 53 प्रतिशत बढ़कर रुपए 1,097 करोड़ से बढ़कर रुपए 1,677 करोड़ है। स्प्रेड 93 बेसिस पाइन्ट बढ़कर 2.15 प्रतिशत से बढ़कर 3.08 प्रतिशत है। एनआईएम 76 बेसिस पाइन्ट बढ़कर 3.85 प्रतिशत से बढ़कर 4.61 प्रतिशत है।

अतः समग्र रूप से आरबीआई की मानीटरी पॉलिसी के अपवर्ड पूर्वाग्रह से न्यूट्रल अथवा ब्याज की दरों के डाउनवर्ड पूर्वाग्रह को बदलते हुए हमारे स्प्रेड्स तथा मार्जिन्स में सुधार हुआ है।

हमने पिछले वर्ष घोषित 50 प्रतिशत अंतरिम लाभांश की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013 में 60 प्रतिशत अंतरिम लाभांश की घोषणा की है।

पिछली सम्मेलन कॉल में, हमने जो वादा किया था, उसके अनुसार हमने स्टेण्डर्ड सम्पत्तियों के लिए प्रावधान किया है। वित्तीय वर्ष 2013 की प्रथम तीन तिमाहियों के लिए रुपए 92 करोड़, जो कि दिनांक 31 दिसम्बर 2012 को स्टेण्डर्ड सम्पत्तियों का 0.06 प्रतिशत है, का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2013 की तीसरी तिमाही में किया गया है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2013 की रिपोर्टाधीन तीसरी तिमाही का लाभ रुपए 92 करोड़ के इस प्रावधान के उपरांत है। यदि हमने यह प्रावधान नहीं किया होता, तो वास्तविक पीएटी 10 प्रतिशत तक ज्यादा होता।

इस तिमाही में कोई नया एनपीए नहीं शामिल किया गया है। पुराने एनपीए जैसे आरएस इण्डिया, श्री महेश्वर, कोनासीमा, एम्पी पावर तथा ओम शक्ति सतत् रखे गए हैं। तथापि, आरएस इण्डिया ने पिछले वर्ष बहुत अच्छा परफार्म किया है तथा इन्होंने 01 जनवरी 2012 से आज दिनांक तक सभी भुगतान कर दिए हैं। इसलिए यह लेखे एक मानक सम्पत्ति हैं अर्थात् जनवरी 2013 के बाद इन्हें परफार्मिंग सम्पत्ति में बदल दिया जाएगा तथा आज दिनांक तक किए गए सभी प्रावधानों को वापिस ले लिया जाएगा। यहाँ एक छोटा एनपीए खाता भी है,

जिसे एमपी पावर कहा जाता है, को यदि रुपए 5 करोड़ का भुगतान किया जाए, तो उसे परफार्मिंग सम्पत्ति में बदला जा सकता है तथा हम इस दिशा में हमारे सभी प्रयास कर रहे हैं।

जहां तक कोनासीमा का सम्बन्ध है, एप्टेल आदेश रिजर्व है तथा वह सीडीआर के लिए गया है। सीडीआर पैकेज की घोषणा के बाद हम भी उसके अनुसार निर्णय लेंगे। महेश्वर के मामले में मध्य प्रदेश सरकार को हमने वैकल्पिक चुनाव दिया है, ताकि पावर प्रोजेक्ट की लागत को प्रभावी बनाया जा सके। हम उनके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

दिनांक 31 दिसम्बर 2012 को सकल एनपीए रुपए 1,363 करोड़ है तथा हमने रुपए 1,568 करोड़ का प्रावधान किया है अर्थात् 1,424 करोड़ के सामान्य प्रावधान (जिसमें संदेहप्रद ऋण हेतु रुपए 1,332 करोड़ तथा मानक सम्पत्तियों हेतु रुपए 92 करोड़ के प्रावधान शामिल हैं) तथा रुपए 144 करोड़ के विशिष्ट प्रावधान हैं, का प्रावधान रखा है।

ट्रांजिशनल फण्डिंग छः राज्यों के डिस्काम्स को दी गई है। कुल आवंटित राशि रुपए 19,630 करोड़ थी, किन्तु चूंकि आन्ध्र प्रदेश ने कोई स्वीकृति की मांग नहीं की, स्वीकृति की कुल राशि रुपए 16,630 करोड़ है। कुल स्वीकृति का ब्यौरा इस प्रकार है:- पंजाब – रुपए 1,000 करोड़, हरियाणा – रुपए 4,300 करोड़, उत्तर प्रदेश – रुपए 1,830 करोड़, राजस्थान – रुपए 4,500 करोड़ तथा तमिनाडु – रुपए 5,000 करोड़। हमने दिसम्बर 2012 तक कुल रुपए 8,211 करोड़ का भुगतान किया है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:- पंजाब – रुपए 600 करोड़, हरियाणा – रुपए 2,580 करोड़, उत्तर प्रदेश – रुपए 1,281 करोड़, राजस्थान – रुपए 2,250 करोड़ तथा तमिनाडु – रुपए 1,500 करोड़।

वित्तीय वर्ष 2013 के 09 माहों में, हमने रुपए 1,110 करोड़ के फ्री बॉण्ड्स, 250 मिलियन डालर के ईसीबी व रुपए 3,723 करोड़ के सीपी सहित कुल मिलाकर रुपए 23,472 करोड़ के बॉण्ड्स उगाहे हैं। इसकी संभावना है कि हम टेक्स फ्री बॉण्ड्स एलोकेशन की शेष राशि रुपए 3,890 करोड़ मार्च 2013 में उगाह लेंगे, जो कि बाजार की स्थितियों पर निर्भर है तथा इस श्रेणी में हम जो भी राशि उगाह सकेंगे, वह हमारे मार्जिन को बढ़ाएगी।

हमने 01 बिलियन डालर के एमटीएन प्रोग्राम का रोड़-शो भी आयोजित किया है। जैसे ही कूल-ऑफ अवधि समाप्त होगी, हम फिर से इश्यू की प्राइसिंग का प्रयत्न करेंगे। हमने 250 मिलियन डॉलर के दूसरे ईसीबी की योजना भी तैयार की है, जिसके लिए दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

जहां तक पी.ई. फण्ड की बात है, टाटा केपिटल के साथ जे.वी. एग्रीमेंट की चर्चा हुई है तथा इसे अंतिम रूप दिए जाने के उपरांत हस्ताक्षरित किया जाएगा।

हमें आरबीआई द्वारा प्रूडेन्शियल नार्म्स तथा कुछ केपिटल एडीक्वेसी नार्म्स से 31 मार्च 2013 तक छूट प्रदान की गई है तथा अब रोडमैप प्रस्तुत करने का समय है।

जहां तक सब्सीडीरीज्/सहायकों की बात है, पीएफसीसीएल के पास रूपए 116 करोड़ के असाइन्मेंट/कार्य हैं। पीएफसी-सीएएस तथा पीएफसी ग्रीन एनर्जी ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। पीएफसी ग्रीन एनर्जी ने दिनांक 01 अक्टूबर 2012 से आरबीआई एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त कर लिया है।

यूएमपीपी के मामलों में हम विद्युत मंत्रालय से एसबीडी दस्तावेजों के पुनरीक्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आईटीपी के मामलों में, चार पहले ही अंतरित हो चुकी है तथा 05वीं आईटीपी (डीजीईएन ट्रांसमिशन कं0 लि0) के लिए अक्टूबर 2012 में आरएफक्यू जारी किया जा चुका है तथा विद्युत मंत्रालय ने पीएफसीसीएल को फिर से चार नई आईटीपी के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक के तौर पर नियुक्त किया है।

ए-पीडीआरपी स्वीकृतियों की स्थिति निम्न प्रकार से है:- भाग-ए (आईटी) - 100 प्रतिशत एससीएडीए - लगभग 98 प्रतिशतय पार्ट बी - 97 प्रतिशत तथा भुगतान की स्थिति निम्न प्रकार से है:- भाग ए (आईटी) - 35 प्रतिशत एससीएडीए - 29 प्रतिशत पार्ट बी - 48 प्रतिशत। 1,332 शहरों के लिए रिंग फेन्सिंग की जा चुकी है अर्थात् 95 प्रतिशत तथा 845 शहरों के लिए बेसलाईन डाटा स्थापित किए जा चुके हैं अर्थात् 60 प्रतिशत। 243 शहरों को डाटा सेन्टर से जोड़ा जा चुका है। 111 शहरों में गो-लाइव को एक्टिव किया जा चुका है। पार्ट - बी से पहले चार राज्यों के 95 शहरों में एटीएण्डसी नुकसान को 10 प्रतिशत तक कम किया गया है।

अब हम पावर क्षेत्र के कुछ मुख्य विकास पर चर्चा करते हैं, जिनका असर पीएफसी पर होता है। 10 राज्यों ने वित्तीय वर्ष 2013 व वित्तीय वर्ष 2014 में प्रशुल्क के पुनरीक्षण हेतु प्रशुल्क याचिका दाखिल की हैं। सरकार ने डिसकाम के नुकसान को कम करने, कार्यक्षमता में सुधार लाने तथा डिसकाम के लिए फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज (एफआरपी) के प्रस्ताव हेतु कदम उठाए हैं। सरकार ने एफआरपी को 05 अक्टूबर 2012 को अधिसूचित किया है तथा यह योजना 31 दिसम्बर 2012 तक लागू थी। अब यह समय सीमा 31 मार्च 2013 तक बढ़ा दी गई है। दिसम्बर 2012 तक सिर्फ तमिलनाडु ने अपनी सरकार व विनियामक से अनुमति लेकर एफआरपी लिया है तथा विद्युत मंत्रालय में प्रस्तुत

किया है। उन्होंने एफआरपी की पुर्नसमीक्षा के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन भी किया है।

एफआरपी स्कीम योजना के तहत 31 मार्च 2012 को बकाया एसटीएल का 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा तथा शेष 50 प्रतिशत को मोरेटोरियम आन प्रिन्सीपल रिपेमेंट के साथ ऋण को रिशेड्यूल करते हुए रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। निवेशक आरबीआई से यह जानकारी चाहते थे कि राजस्थान, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां बैंकों ने दिसम्बर 2012 तक रिस्ट्रक्चरिंग किया है, क्या वहां एफआरपी योजना के तहत फिर से मार्च 2013 तक होने वाले रिस्ट्रक्चरिंग को रिपीटेड रिस्ट्रक्चरिंग माना जाएगा। आर.बी.आई. ने यह स्पष्ट किया है कि इन्हें मानक सम्पत्ति माना जाएगा।

हांलॉकि, एफआरपी, डिस्काम के प्रचालन निष्पादन को सुधारने हेतु, डिस्काम तथा राज्य सरकार की ठोस तथा परिमेय कार्रवाई की शर्त के अधीन है। इसमें कुल 07 अनिवार्य शर्तें हैं, जिन्हें पूरा किया जाना होंता है तथा सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि राज्य सरकार को विद्युत मंत्रालय द्वारा मॉडल कानून के परिचालन की तिथि से 12 माह की अवधि के अंदर एफआरपी के प्रावधानों का अनुपालन अनिवार्य करने हेतु कानून अधिनियमित करना होगा। राज्यों की वित्तीय स्थिति पर इसके असर की प्रभावी निगरानी के लिए एफआरपी को राज्य के वार्षिक बजट स्टेटमेंट का हिस्सा बनाना होगा। एक बार राज्य द्वारा यह कानून अधिनियमित कर दिया जाएगा, तो विश्वसनीयता के लिए यह दायित्व होगा कि चाहे कोई भी राजनैतिक पार्टी राज्य में सत्ता में रहे, इस कानून का अनुपालन किया जाएगा।

फिर भी डिस्काम की प्रगति की निगरानी के लिए राज्य तथा केन्द्र स्तर की समितियों का गठन किया जाएगा। केन्द्रीय समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है। केन्द्र सरकार द्वारा आर-एपीआरडीपी स्तर से अधिक बचाई गई अतिरिक्त एनर्जी के मूल्य के समतुल्य अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रिन्सीपल रिपेमेंट का 25 प्रतिशत (राज्य सरकार द्वारा दायित्वों को ग्रहण किए जाने के आधार पर) पूंजी प्रतिपूर्ति आधार के तौर पर उपलब्ध कराया जाएगा। पीएफसी तथा आरईसी ने लगभग रुपए 35,000 से 40,000 करोड़ का ट्रांजीशनल फाइनेंस, पहचान किए गए छः राज्यों की डिस्काम्स को फण्डिंग हेतु उपलब्ध कराया है। जैसा की पहले उल्लिखित किया गया है, इन छः राज्यों में से सिर्फ पाँच राज्य यथा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु तथा राजस्थान स्वीकृतियों के लिए हमारे पास आए हैं, जबकि आन्ध्र प्रदेश ने कोई स्वीकृति नहीं माँगी है। हम प्रत्येक राज्य की एफआरपी के आधार पर बेलेंस केश गेप की फण्डिंग करेंगे तथा भुगतान को रिफार्म माइलस्टोन्स के साथ जोड़ दिया जाएगा।

10 राज्यों ने पहले ही वित्तीय वर्ष 2013 व वित्तीय वर्ष 2014 में प्रशुल्क के पुनरीक्षण हेतु प्रशुल्क याचिका दाखिल की हैं। आर-एपीडीआरपी योजना, एटीएण्डडी नुकसान को कम करने में भी सहायक है। वस्तुतः विद्युत मंत्रालय, पीएफसी तथा योजना आयोग द्वारा इसे अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है तथा मासिक तथा कभी-कभी द्विमासिक बैठकों का आयोजन यह सुनिश्चित करने हेतु किया जा रहा है कि आर-एपीडीआरपी की प्रगति ठीक से हों तथा रिंग-फेन्सिंग व साथ ही साथ आनलाईन डाटा सेंटर को जोड़ने का कार्य समय पर पूर्ण हों।

जहां तक कोल एफएसए का सम्बन्ध है, कोल इण्डिया ने 114 एफएसए में से 42 एफएसए पहले ही हस्ताक्षरित कर लिए हैं तथा शेष को भी शीघ्र ही हस्ताक्षरित किए जाने की आशा है। खबरों के मुताबिक निवेश पर मंत्रिमण्डल समिति (सीसीआई) एफएसए, रुपए 1000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं तथा कोल पूल प्राइसिंग के मामलों पर चर्चा करनेवाली है। इसलिए हमें इस स्थिति में सुधार की आशा है।

दूसरा नई प्रगति यह है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पावर कंपनियों को अधिकतम प्रचालन अर्जित करने हेतु, उनके एक प्लांट से दूसरे प्लांट में प्राकृतिक गैस डायवर्ट करने की अनुमति दी जाए व कठोर/स्ट्रिन्जेंट पॉलिसी, जो विशेष यूनिट्स को फ्यूल आपूर्ति प्रतिबंधित करती हैं, को रिलेक्स किया जाए।

सीआईएल तथा एसईसीएल से कोल ऑफटेक टू पावर में भी सुधार हुआ है। अप्रैल - नवम्बर 12 में यह लगभग 237 मिलियन टन है, जिसमें पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।

क्षमता विस्तार में भी विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं, जैसा कि पिछले वर्षों के आँकड़ों से देखा जा सकता है। वर्षानुसार क्षमता विस्तार का ब्यौरा निम्न प्रकार है:- 9,585 एमडब्ल्यू वित्तीय वर्ष 2009-10, 12,161 एमडब्ल्यू वित्तीय वर्ष 2010-11, 20,502 एमडब्ल्यू वित्तीय वर्ष 2011-12, 9,854 एमडब्ल्यू वित्तीय वर्ष 2012-13 (अप्रैल-दिसम्बर 2012) वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए क्षमता लक्ष्य 17,956 एमडब्ल्यू निर्धारित किया गया है। 12वीं योजना के मामले में क्षमता विस्तार लक्ष्य लगभग 88,537 एमडब्ल्यू है तथा रिन्यूबल एनर्जी से 30,000 एमडब्ल्यू की अतिरिक्त क्षमता प्रस्तावित है।

वित्त की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रगति, जिसका पीएफसी पर असर होगा, वह है, गैर बैंकीय वित्त कंपनियों के लिए आरबीआई की ड्राफ्ट गाइडलाइन्स। गाइडलाइन्स के अनुसार न्यूनतम टीयर-1 पूंजी 10 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत होनी चाहिए तथा हम पहले ही इस आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। गाइडलाइन्स में क्लासीफाइंग ऋण को एनपीए में परिवर्तित करने की अवधि को वर्तमान नार्म से 90 दिन चरणबद्ध तरीके से किए जाने हेतु भी प्रस्तावित किया

गया है, लेकिन हमने आरबीआई से अनुरोध किया है कि वर्तमान मानक को कम से कम पीएफसी के लिए बनाए रखा जाए, क्योंकि हमारी वसूलियाँ विकासकों को डिस्कॉम्स से उनके भुगतान प्राप्त होने से जुड़ी हुई हैं, जो कि पीपीए इत्यादि पर आधारित हैं। इसलिए हम अभी भी इस पर जोर दे रहे हैं कि हमें 180 दिन के मानक के अनुपालन की अनुमति दी जाए। हमने आरबीआई को तीन और मामलों पर भी अपनी टिप्पणी दी है:- 1) मानकीकृत प्रावधान में मार्च 2014 से 0.25 से 0.40 की वृद्धि, 2) सभी सरकारी कम्पनियाँ, जो एनबीएफसी पात्र हैं, पर एनबीएफसी हेतु लागू विनियामक फ्रेमवर्क के अनुपालन की आवश्यकता, 3) 01-30 दिन में नेगेटिव गेप, केश आउटप्लो के 15 प्रतिशत से अधिक न हों, को सुनिश्चित करने के लिए एएलएम की आवश्यकता।

इस तिमाही में हमें कुछ अवार्ड भी मिले हैं, यथा – जेजीबीएस टॉप रैंकर्स एक्सीलेंस अवार्ड तथा आईसीसी पीएसई एक्सीलेंस अवार्ड।

इस प्रकार से यह कुछ मुख्य वित्तीय, व्यावसायिक तथा सेक्टरल हाईलाइट्स (पावर क्षेत्र के साथ-साथ वित्तीय क्षेत्र दोनों से) हैं, जो पीएफसी को प्रभावित करते हैं। अब मैं विश्लेषकों के प्रश्नों का जवाब दूँगा।

मर्यादक बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय। देवियों एवं सज्जनों अब हम प्रश्नोत्तर के सत्र की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न पूछने के लिए यूटीआई म्यूचुअल फण्ड के श्री अमित प्रेमचंदानीजी का स्वागत है। कृपया आप अपना प्रश्न पूछें।

अमित प्रेमचंदानी क्या आप राज्यों के बीच ट्रान्जिशनल फाइनेंस, स्वीकृतियों तथा भुगतान को दोहराएंगे?

आर. नागराजन कुल स्वीकृतियों का ब्यौरा इस प्रकार है:- पंजाब – रुपए 1,000 करोड़, हरियाणा – रुपए 4,300 करोड़, उत्तर प्रदेश – रुपए 1,830 करोड़, राजस्थान – रुपए 4,500 करोड़ तथा तमिनाडु – रुपए 5,000 करोड़, आन्ध्र प्रदेश ने स्वीकृति का अनुरोध नहीं किया है। कुल भुगतान का ब्यौरा इस प्रकार है:- पंजाब – रुपए 600 करोड़, हरियाणा – रुपए 2,580 करोड़ (दोनों डिस्कॉम्स यथा दोनों दक्षिण हरियाणा तथा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण लिमिटेड), उत्तर प्रदेश – रुपए 1,281 करोड़, राजस्थान – रुपए 2,250 करोड़ (सभी तीनों वितरण कम्पनियाँ यथा अजमेर, जोधपुर तथा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड तथा तमिनाडु – रुपए 1,500 करोड़ (तमिलनाडु जनरेशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड)।

अमित प्रेमचंदानी –इन ऋणों के लिए ब्याज की सामान्य दर तथा जोखिम वेट क्या है?

आर. नागराजन –ब्याज की सामान्य दर लगभग 12.5 प्रतिशत है तथा ये सभी पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त हैं। इसीलिए हमारी पूंजी पर्याप्तता दिसम्बर 2011 के 17.92 प्रतिशत से बढ़कर दिसम्बर 2012 में 18.1 प्रतिशत होने का यह भी एक कारण है।

अमित प्रेमचंदानी –इसलिए इनमें 20 प्रतिशत जोखिम वेट है?

आर. नागराजन –हाँ।

अमित प्रेमचंदानी –महोदय मान लें, यदि आप राज्य विद्युत बोर्ड को 12.5 प्रतिशत पर उधार देंगे तथा मान लें कि आप 4.5 प्रतिशत का मार्जिन लेंगे। क्या आपको उनसे कोई पुशबैक मिला है, क्योंकि वर्तमान परिवेश में 4.5 प्रतिशत का मार्जिन स्वाभाविक रूप से असामान्य है? और जब ब्याज की दरें कम होंगी, क्या तब भी वे 12.5 प्रतिशत की दर से आपको भुगतान करने को तैयार होंगे तथा इस अवस्था में कब तक यह चालू रह पाएंगे?

आर. नागराजन –पीएफसी नीति के अनुसार मान लें, यदि आज एक ऋण स्वीकृत होता है और मान लें कि ब्याज की दर लगभग 12.5 प्रतिशत है, यदि ऋणधारक कल ही भुगतान लेता है, तो उस पर 12.5 प्रतिशत की दर से ब्याज प्रभारित होगा, लेकिन यदि वह एक वर्ष बाद भुगतान लेता है तथा एक वर्ष बाद ब्याज की लागू दर 10 प्रतिशत है तो उस पर 10 प्रतिशत की दर से ब्याज प्रभारित किया जाएगा।

इसलिए जब मार्केट मुझे उच्च लागत ऋण देता है, लगभग तीन महीने पहले 3 वर्ष या 5 वर्ष का उधार लगभग 9.5 प्रतिशत पर था, तब उधार देने की दर भी ठीक थी। लेकिन अब बॉण्ड से होनेवाला लाभ भी एकदम से नीचे लगभग 8.75 प्रतिशत की दर तक हों गया है तथा आरबीआई द्वारा रेट कम करने के बाद हम भी इसकी जांच कर रहे हैं कि क्या ब्याज की दर को कम किया जा सकता है।

अमित प्रेमचंदानी –तो ऋण की अवधि कितनी होंगी और ब्याज कब रिसेट किया जाएगा?

आर. नागराजन –आरबीआई तथा वित्त मंत्रालय द्वारा बैंकों को कहा गया है कि ऋण की विलम्बन अवधि (मोरटोरियम) तीन वर्ष तथा पुनर्भुगतान सात वर्ष होना चाहिए। इसलिए सभी ट्रान्सीजशनल फण्डिंग, जो हम कर रहे हैं, के लिए इसमें पहले तीन वर्ष ब्याज के भुगतान करना होगा तथा मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए मोरटोरियम होगा, जबकि तीन वर्ष के बाद उन्हें मूलधन तथा ब्याज दोनों का भुगतान करना होगा।

अमित प्रेमचंदानी—ब्याज रिसेट, यह 12.5 प्रतिशत क्या प्रत्येक तिमाही में रिसेट होगा या रिसेट किस प्रकार से किया जाएगा?

आर. नागराजन—03 वर्ष ।

अमित प्रेमचंदानी—रिसेट तीन वर्ष बाद होगा?

आर. नागराजन मान लें, ऋणकर्ता ने अगस्त 2012 में ऋण लिया है, तो पहला रिसेट अगस्त 2015 में होगा। बाद के सभी भुगतान भी, मान लें कि भुगतान नवम्बर 2012, दिसम्बर 2012 तथा अप्रैल 2013 में हुए, सभी को आपस में जोड़ लिया जाएगा तथा रिसेट अगस्त 2015 में एक साथ ही होगा, इस प्रकार से रिसेट पहले भुगतान की तिथि से तीन वर्ष बाद होगा।

अमित प्रेमचंदानी—और सामान्य तौर पर महोदय, आपको क्या आशा है 4.6 प्रतिशत तथा 3 प्रतिशत व स्प्रेड के कारण मार्जिन आउटलुक बढ़ रहा है? क्या आप सोचते हैं कि क्या ये बना रहेगा या हम फ्लेट 2.5 प्रतिशत से मूव करेंगे?

आर. नागराजन—जैसा मैंने पहले कहा है, मार्जिन लगभग 2.5 प्रतिशत रहेगा लेकिन हमारा लक्ष्य आनेवाले समय में इसमें सुधार लाने का है।

अमित प्रेमचंदानी—अगली 02 तिमाहियों में कितनी सम्पत्तियों की रिप्राइसिंग होगी और इसी प्रकार से देयताएं भी?

आर. नागराजन—अगले वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2013-14 में लगभग रुपए 48,735 करोड़ की सम्पत्तियों व लगभग रुपए 39,788 करोड़ की देयताओं की रिप्राइसिंग रिसेट के रिपीटेशन को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

अमित प्रेमचंदानी—रिस्ट्रक्चरिंग की पाइपलाइन में मूलतः हांल ही में एक एकाउंट, सुज़लान को सीडीआर के प्लेटफार्म पर रिस्ट्रक्चर किया गया है। आपको भी इस एकाउंट की स्थिति की जानकारी है। क्या आप रिस्ट्रक्चरिंग की शर्तों का स्पष्ट करेंगे तथा आप किस प्रकार से इसे एकाउंट फार करेंगे?

आर. नागराजन—हमने सुज़लान के प्रबंधन को पहले ही बता दिया है कि भले ही सभी बैंक रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। यदि वे सभी देय राशि का भुगतान करेंगे, तो ही हम कुछ सोच सकते हैं। हम उन्हें मूलधन के पुनर्भुगतान को आगे बढ़ाने की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन ब्याज की दर में हम कोई कमी नहीं करेंगे। पहले हमने जो भी रिस्ट्रक्चरिंग की है, जैसे कि आरएस इण्डिया या एमपी पावर के मामले में, हमने ब्याज की दर में कोई कमी नहीं की है। हम नकदी प्रवाह (केश फ्लो) की व्यवस्था हेतु रिपेमेंट को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं।

अमित प्रेमचंदानी—तो यदि सुज़लान की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कोई शर्त है, तो वह क्या है?

आर. नागराजन—यदि वे रोकड़ प्रवाह (केश पलो) की व्यवस्था के लिए पुनर्भुगतान को छः महीने के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम विचार कर सकते हैं, लेकिन ब्याज की दर को कम किए बिना।

अमित प्रेमचंदानी—तो क्या आपको ब्याज का भुगतान भी नकद में करना होगा, क्योंकि कुछ बैंकों ने 2 वर्ष का ब्याज भी दिया है?

आर. नागराजन—मैं जानता हूँ कि बैंकों ने 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर के मोरटोरियम, मूलधन मोरटोरियम तथा इक्विटी के रूप में ब्याज के भुगतान के मोरटोरियम की अनुमति भी दी है। तथापि हमने सुज़लान के उच्च प्रबंधन को स्पष्ट कर दिया है कि हमें ब्याज का भुगतान नकद चाहिए तथा हम उनके नकद प्रवाह को मेच करने के लिए सिर्फ मूलधन पुनर्भुगतान पर विचार कर सकते हैं।

अमित प्रेमचंदानी—महोदय, आपके लिए सुज़लान का एक्सपोज़र (की स्थिति) क्या है?

आर. नागराजन—रुपए 934 करोड़।

अमित प्रेमचंदानी—रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अन्य कोई पाईपलाइन, जो आपके पास हों?

आर. नागराजन—आज की तिथि में कोई नहीं।

मर्यादक —धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न एवेन्डस सिक्यूरिटीज से आए जयनी शाह का है। कृपया आप अपना प्रश्न पूछें।

जयनी शाह —पहले पूछे गए प्रश्नों के फॉलोअप के तौर पर जानना चाहेंगे कि आज की तिथि में बकाया रिस्ट्रक्चर्ड परिसंपत्तिया क्या हैं, यदि आप वह राशि हमें बताना चाहें?

आर. नागराजन—यह लगभग रुपए 4,984 करोड़ है।

जयनी शाह —एसईबी के इस फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम के संबंध में हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि इसकी शर्तों से सहमति के संबंध में राज्यों की कितनी इच्छुकता है?

आर. नागराजन—जैसा कि मैंने अपनी शुरुआती टिप्पणी में बताया है तमिलनाडु ने राज्य मंत्रिमंडल तथा विनियामकों से सैद्धांतिक अनुमोदन ले लिया है तथा केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर दिया है तथा इस योजना के अनुसार समिति का गठन भी कर दिया है। समाचार पत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश ने भी मंत्रिमंडल से अनुमोदन ले लिया है तथा इस प्रस्ताव के लिए केन्द्र सरकार के पास जाने से पूर्व उन्हें विनियामक के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। मैं सोचता हूँ कि हरियाणा और राजस्थान भी मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के सम्पर्क में है। इस प्रकार से कम से कम 3 राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा एफआरपी के अनुपालन हेतु इच्छुक हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश एफआरपी का इच्छुक नहीं है तथा पंजाब केन्द्र सरकार के एफआरपी में इच्छुक नहीं है।

- मर्यादक धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न बैंक ऑफ अमेरिका से आए विकेश गाँधी का है। कृपया आप अपना प्रश्न पूछें।
- विकेश गाँधी सिर्फ कुछ प्रश्न। एक तो कोनासीमा के आपके एक्सपोजर पर है। मेरा विश्वास है कि पिछले वर्ष दिसम्बर में इसे एनपीए के तौर पर मान लिया गया था। इसलिए तकनीकी तौर पर इसे इस तिमाही में आगे लाने/स्टेपअप का प्रावधान नहीं है या इसे अगली तिमाही में लाया जाएगा?
- आर. नागराजन हमने कोनासीमा को एनपीए के तौर पर दिसम्बर 2011 में मान लिया था, इसलिए 18 माह की अवधि समाप्त होने के बाद हम वित्तीय वर्ष 2014 की पहली तिमाही में हम इसे उपलब्ध कराएंगे।
- विकेश गाँधी यह 10 प्रतिशत से कितना जाएगा?
- आर. नागराजन 20 प्रतिशत।
- विकेश गाँधी आपका मतलब है और 10 प्रतिशत।
- आर. नागराजन जी हाँ।
- विकेश गाँधी और महेश्वर की तरफ से?
- आर. नागराजन हमने महेश्वर को मार्च 2012 में उपलब्ध कराया है, इसलिए 18 महीने के बाद हम वित्तीय वर्ष 2014 की दूसरी तिमाही में इसे उपलब्ध कराएंगे।
- मर्यादक धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न इक्वीरस सिक्यूरिटीज से आए देवाँग मोदी का है। कृपया आप अपना प्रश्न पूछें।
- देवाँग मोदी मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा जो फाइनेंस किया जा रहा है, उसमें आपरेशनल तथा एक्जीक्यूशन एसेट्स/सम्पत्ति का प्रतिशत क्या है?
- आर. नागराजन उत्पादन परिसंपत्तियों का बकाया रूपए 1,21,181 करोड़ है जिसमें से कमीशनड संपत्तियां रूपए 33,787 करोड़ है।
- देवाँग मोदी महोदय, जिन परियोजनाओं में हमारे द्वारा फाइनेंस किया जा रहा है, एमडब्ल्यू के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014 तथा वित्तीय वर्ष 2015 में कितनी राशि की उत्पादन परिसंपत्तियों की आशा है?
- आर. नागराजन वास्तव में हमारे पास एमडब्ल्यू का ब्यौरा नहीं है। जहां कमीशनिंग होनेवाली है, वहां ऋण संपत्तियों का राशिवार ब्यौरा निम्न प्रकार से है:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में रूपए 11,306 करोड़, वित्तीय वर्ष 2015-16 में रूपए 569 करोड़, वित्तीय वर्ष 2016-17 में रूपए 2,417 करोड़।

- देवांग मोदी इसके अलावा सिर्फ यह जानना चाहूँगा कि भुगतान के अनुसार इस तिमाही में किए गए ट्रान्जीशनल ऋण की राशि कितनी है?
- आर. नागराजन हमने वित्तीय वर्ष 2013 की तीसरी तिमाही में रुपए 6,111 करोड़ का भुगतान किया है।
- मर्यादक बहुत-बहुत धन्यवाद। हम अगला प्रश्न एडेलवेस केपिटल से आई सुरुची चौधरी से लेंगे। कृपया आप अपना प्रश्न पूछें।
- सुरुची चौधरी आरएस इण्डिया पर, जैसा आपने बताया कि इसे जनवरी में अपग्रेड किया जाएगा। प्रॉवीजन रिवर्सल के अलावा इंकम रिवर्सल का क्या तरीका हों सकता है, जिसे अपनाया जा सकता है?
- आर. नागराजन हम लगभग 13 प्रतिशत ब्याज प्रभारित कर रहे हैं, इसलिए रुपए 224 करोड़ के लिए हमें रुपए 5-6 करोड़ की अतिरिक्त आय इस तिमाही में एक्रूअल आधार पर होंगी।
- सुरुची चौधरी महोदय, लेकिन आपने बताया है कि एकाउन्ट की सर्विसिंग पिछले एक वर्ष से की जा रही है। इसलिए इस अवधि में ब्याज की सर्विसिंग भी हुई होंगी?
- आर. नागराजन सर्विस्ड ब्याज को केश के आधार पर खातों में लिया जाता है। एक्रूअल बेसिस पर 02 जनवरी 2013 से 31 मार्च 2013 तक ब्याज निकाला गया है, जो कि लगभग रुपए 5-6 करोड़ होंगा।
- सुरुची चौधरी और इस 230 करोड़ पर जो 10 प्रतिशत की प्रॉविजनिंग की गई है, इसलिए रुपए 23 करोड़ रिवर्सड हों जाएंगे?
- आर. नागराजन जी हाँ, रुपए 224 करोड़ के ऋण के विरुद्ध रुपए 22 करोड़ को रिवर्सड कर उपलब्ध कराया जाएगा।
- सुरुची चौधरी ट्रान्जीशनल फाइनेंसिंग भुगतान के तौर पर, आपके द्वारा आज तक रुपए 16,000 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है?
- आर. नागराजन नहीं, हमने वित्तीय वर्ष 2013 की तीसरी तिमाही में रुपए 6,111 करोड़ का भुगतान किया है तथा वित्तीय वर्ष 2013 के 09 माह में 8,211 करोड़ का भुगतान किया है।
- सुरुची चौधरी महोदय, क्या यह वह भुगतान है, जो पिछली दो तिमाहियों में किया गया है?
- आर. नागराजन जी हाँ, अब तक ट्रान्जीशनल फाइनेंस में रुपए 8,211 करोड़ का भुगतान किया है।
- सुरुची चौधरी स्वीकृतियों के ब्यौरे के अनुसार, जो आपने अंदाजन रुपए 16,000 करोड़ की दी हैं, क्या आज दिनांक तक दी गई स्वीकृतियों की कुल राशि यही है?

आर. नागराजन जी हॉ, हमने रुपए 16,630 करोड़ की स्वीकृतियाँ दी हैं तथा 31 दिसम्बर 2012 तक रुपए 8,211 करोड़ का भुगतान किया है।

सुरुची चौधरी क्या हम आगे और भी स्वीकृतियाँ देख सकेगे या तत्काल एक या दो तिमाही में नहीं, लेकिन....?

आर. नागराजन 05 एसईबी, जिन्हें हमने ट्रांजीशनल फाइनेंस दिया है, की बहुत सारी परेशानियाँ/इश्यूज़ हैं तथा इनके नुकसान के आँकड़ों का योग कुल नुकसान का 50-60 प्रतिशत है। इसको ध्यान में रखते हुए, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई दूसरा इस योजना के लिए आएगा।

सुरुची चौधरी इस प्रकार प्रशुल्क पुनरीक्षण याचिका देकर, जो उन्होंने फाईल की हैं, वे इसके बाद उनके फाइनेंस को आगे बढ़ाने की व्यवस्था कर पाएंगे?

आर. नागराजन जी हॉ, क्योंकि समाचार पत्रों में आई खबरों के आधार पर कुछ राज्यों ने 7 प्रतिशत से 59 प्रतिशत की सीमा तक प्रशुल्क पुनरीक्षण प्रस्तावित किया है। विभिन्न राज्यों द्वारा फाईल किए गए प्रशुल्क पुनरीक्षण का ब्यौरा इस प्रकार से है:- आन्ध्र प्रदेश द्वारा 15 से 20 प्रतिशत, हरियाणा द्वारा 46 प्रतिशत, केरल द्वारा 18 से 19 प्रतिशत, मध्य प्रदेश 20 से 27 प्रतिशत, नागालैंड द्वारा 07 प्रतिशत, पंजाब द्वारा 59 प्रतिशत और राजस्थान द्वारा 10 से 13 प्रतिशत। दिल्ली, उड़ीसा और जम्मू व कश्मीर ने भी प्रशुल्क पुनरीक्षण फाईल किया है।

सुरुची चौधरी आपने बताया है कि आपका यह प्रयास है कि आप यहाँ से आगे अब एनआईएम का विस्तार देखेंगे। क्या इसलिए अब हम यह देख रहे हैं कि आप मुख्य रूप से लागत लाभ की तरफ जा रहे हैं। हमने देखा है कि इस तिमाही में भी लागत कम हुई है या आप यह आशा करते हैं कि यहाँ से आगे अब सम्पत्तियों पर भी मुनाफे में वृद्धि होगी?

आर. नागराजन हम तीन रिसोर्स मोबीलाइजेशन कार्यक्रमों से लागत को कम होना देख रहे हैं। सबसे पहले, टेक्स फ्री बॉण्ड से लाभ, जो हमने वित्तीय वर्ष 2013 की तीसरी तिमाही के अंतिम महीने में पाया है, इसका पूरा लाभ अगली तिमाही अर्थात् वित्तीय वर्ष 2013 की चौथी तिमाही में मिलेगा। दूसरा, हमारे कर मुक्त बॉण्ड आवंटन के शेष से लाभ होगा। तीसरा, हम वित्तीय वर्ष 2013 की चौथी तिमाही में 250 मिलीयन डॉलर की ईसीबी की योजना बना रहे हैं, उससे भी लाभ होगा। हमने ईसीबी के लिए मर्चेन्ट बैंकर की नियुक्ति भी कर दी है। 01 बिलियन डॉलर के एमटीएन प्रोग्राम के लिए रोड़-शो पहले ही किए जा चुके हैं तथा जैसे ही कूल ऑफ अवधि पूरी होगी, वैसे ही प्राईसिंग की जाएगी। घरेलू बाजार में भी ब्याज की दरों में मंदी आई है, जैसा कि बॉण्ड्स से हुए लाभ लगभग 8.7 से 8.75 प्रतिशत से देखा जा सकता है। फिर भी संपत्ति के लिए रिसेट पहले ही हो चुका है। इसमें रुपए व डॉलर का मूल्यांकन भी है अर्थात् दिसम्बर 2012 में

यह लगभग रूपए 55 था और आज यह लगभग रूपए 53.27 है। हमारे पोर्टफोलियो में 500 मिलियन डॉलर के समतुल्य येन ऋण भी है, जिसमें दिसम्बर 2012 में येन/डॉलर की दर 85.55 थी, जो अब लगभग 91 है। इसलिए विदेशी करेंसी दायित्वों के पोर्टफोलियो में हम भले ही कोई हेजिंग/बचाव नहीं कर पा रहे हैं, पर हमें मार्केट-टू-मार्केट बेसिस पर लाभ होगा। इसलिए इन सभी कारणों से अगली तिमाही में हमें बहुत लाभ होगा।

- सुरुची चौधरी क्या हम यील्ड/फायदे पर बनेफिट में भी आगे बढ़ने जा रहे हैं?
- आर. नागराजन आरबीआई के रेट कट के बाद हम भी इसकी जाँच कर रहे हैं कि क्या ब्याज की दर को कम किया जा सकता है।
- मर्यादक बहुत-बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न हम एचडीएफसी म्युचुअल फण्ड के आनंद लाधा से लेंगे। कृपया आप अपना प्रश्न पूछें।
- आनंद लाधा एसईबी ट्रांजीशनल फाइनेंस पर हम सिर्फ यह समझना चाहते हैं कि रूपए 16,000 करोड़ की स्वीकृति का आधार क्या है, क्या यह कि वे वर्तमान नुकसान के गेप को फण्ड करेंगे, ताकि पीएफसी, आईसीसी भी समतुल्य तरीके से फण्डिंग करें तथा बैंकों द्वारा भी कुछ अनुपात में फण्ड किया जाए?
- आर. नागराजन अधिकतर बैंकों द्वारा पहले जो रिस्ट्रक्चरिंग की गई है, उनमें उन्होंने 03 वर्ष को मॉनीटोरियम तथा 07 वर्ष को प्रिंसीपल पुनर्भुगतान प्रस्ताव किया है। हमने भी कुछ उप-शर्तें रखी हैं। कुछ राज्यों में आप इसका असर भी देख पा रहे हैं, जैसे तमिलनाडु, जिसने पहले ही 2003-2010 में प्रशुल्क लगभग 37 प्रतिशत बढ़ाया था, बहुत ही शीघ्र अगली प्रशुल्क याचिका फाईल करने की योजना बना रहा है तथा उसने राज्य मंत्रिमंडल से एफ.आर.पी. का अनुमोदन भी ले लिया है। स्टेट केबिनेट अनुमोदन के अनुसार हर साल जो भी कमी/शार्टफॉल रहेगा, उसे राज्य सरकार द्वारा फण्ड किया जाएगा। विनियामक (ईआरसी) भी तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एफआरपी से सहमत है। इस प्रकार से तमिलनाडु में यह एक बहुत बड़ा चेंज है तथा सब कुछ केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए समय अर्थात् 31 दिसम्बर 2012, से पहले पूरा कर लिया जाएगा। अन्य राज्य भी प्रशुल्क को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी यह महसूस किया है कि प्रशुल्क को बढ़ाए बिना आप इसे नहीं चला सकते हैं।
- आनंद लाधा मेरा प्रश्न यह समझने के लिए है, कि मान लें एसईबी को नुकसान होता है, तो ट्रांजीशनल नुकसान, ब्रेकईवन ऑफ होने की अवधि से पहले, मान लें यह रूपए 100 करोड़ है, तो पीएफसी, आरईसी तथा बैंक्स इससे सहमत हैं कि इस नुकसान को अनुपात के आधार पर फण्ड करेंगे तथा यह रूपए 16,000 करोड़ की स्वीकृति इसी का एक भाग है।

आर. नागराजन राज्य विद्युत वितरण कंपनियों को होने वाले कुल नुकसान का अनुमान रूपर 1,90,000 करोड़ आँका गया है। नुकसानों को या तो राज्य सरकार द्वारा फण्ड किया जाएगा या फिर ऋणदाता/लेण्डर द्वारा फण्ड किया जाएगा।

आनंद लाधा इस स्थिति में बैंक द्वारा भी ब्याज की वही दर प्रभारित की जाएगी?

आर. नटराजन हम कुछ राहत उपलब्ध कराएंगे, ताकि कुछ समय बाद वे वापिस आ सकें तथा हमने हर साल प्रशुल्क बढ़ाने तथा प्रशुल्क याचिका फाईल कर सकने जैसी कुछ विशिष्ट शर्तों का प्रावधान किया है। संभव है कि 06 राज्यों में से 04 राज्य तीन सालों में इसके लिए आएंगे। अगले वित्तीय वर्ष 2014 में पंजाब पहले ही केश सरप्लस पर चर्चा कर रहा है।

आनंद लाधा महोदय, हम सिर्फ यह समझना चाहते हैं कि जब आप यह कहते हैं कि हम लगभग 12.25 प्रतिशत प्रभारित करेंगे, तो क्या यह बेसिक तथा कुछ स्प्रेड जैसी आंतरिक तरीकों से जुड़ा है? तो आपका बेस रेट क्या होगा अथवा इस प्रकार से आपका उधार देने का रेट क्या होगा तथा इस पर स्प्रेड क्या होगा?

आर. नागराजन जब से पीएफसी शुरू हुआ है, हमने कोई बेस रेट नहीं रखा है। लेण्डिंग का हमारा सिस्टम यह है कि वास्तविक भुगतान की तिथि को लागू ब्याज दर ही हमारी ब्याज दर होती है। यह परियोजना फण्डिंग में बहुत उपयोगी है। समझ लीजिए यदि दर बहुत ज्यादा है, मान लें एग्रीमेंट हस्ताक्षरित करने की तिथि को 16 प्रतिशत है। हम भुगतान की तिथि को 16 प्रतिशत की दर से ब्याज प्रभारित नहीं करेंगे, यदि भुगतान की तिथि को बाजार में ब्याज की दर 8 प्रतिशत हो गई है। इसी प्रकार से मान लें यदि एग्रीमेंट हस्ताक्षरित करने की तिथि को यह 8 प्रतिशत है। हम भुगतान की तिथि को 8 प्रतिशत की दर से ब्याज प्रभारित नहीं करेंगे, यदि भुगतान की तिथि को बाजार में ब्याज की दर 20 प्रतिशत पहुँच गई है। तो इस प्रकार से हम भुगतान की तिथि को जो भी दर लागू होगी, उसी दर से ब्याज प्रभारित करेंगे। साथ ही ऋणधारक को ब्याज की दर रिसेट करने के दो विकल्प देंगे यथा 03 वर्षीय रिसेट व 20 वर्षीय रिसेट। यदि ऋणधारक 03 वर्षीय रिसेट को चुनता है तो 03 वर्षीय रिसेट की तिथि को ब्याज की जो दर लागू होगी, वह बकाया ऋण की पूरी राशि पर लागू होगी। इस प्रकार से आज की तारीख में हम लगभग 12.5 प्रतिशत की दर से ब्याज प्रभारित कर रहे हैं। यदि ब्याज की दर में कमी आती है, तो इसका लाभ ऋणधारक को या तो भविष्य के भुगतानों के लिए मिलेगा या फिर पहले किए गए भुगतानों के लिए, यदि कोई होगा, तो अवश्य मिलेगा।

- आनंद लाधा महोदय, हमारे लिए आपके पास कोई विचार है या जैसे हमेशा हमारा लक्ष्य होता है, स्प्रेड का कोई तरीका, जैसे कि लेण्डिंग के लिए, जैसे यह 12.25 प्रतिशत मेरी पूंजी लागत पर है, के 3 प्रतिशत स्प्रेड अथवा 2 प्रतिशत स्प्रेड?
- आर. नागराजन अप्रैल 2012 में आरबीआई के रेट कट के बाद से किसी ने भी मार्केट में रेट कम नहीं किया है, इसलिए हमने भी जुलाई 2011 के बाद ब्याज की दर में कमी नहीं की है। अब जनवरी 2013 में आरबीआई के रेट कट के बाद हम भी इसकी जाँच कर रहे हैं कि क्या रेट कम किया जाना चाहिए।
- मर्यादक बहुत-बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न हम गोल्डमेन सेक्स के राहुल जैन से लेंगे। कृपया आप अपना प्रश्न पूछें।
- राहुल जैन महोदय, शीघ्रता से सिर्फ 02 प्रश्न। पहला यह कि तीसरी तिमाही में दायित्वों की रिप्राइसिंग कितनी है तथा इन दायित्वों पर रेट कितने नीचे आएंगे?
- आर. नागराजन अधिकतर ऋण या तो बेस रेट या फिर पीएलआर रेट से जुड़े/लिंकड हैं। अप्रैल 2012 में आरबीआई के रेट कट के बाद किसी भी बैंक ने ब्याज की दर कम नहीं की है, इस प्रकार हमारे लिए बेस रेट/पीएल पीएलआर से लिंकड ऋण रेट में इस तिमाही में कोई कमी नहीं है। सिर्फ जहां पर बाण्ड्स एक वर्षीय रिसेट अथवा तीन वर्षीय रिसेट से लिंकड हैं, हमें बॉण्ड यील्ड्स के कम रहने के कारण कुछ फायदा मिलेगा।
- राहुल जैन कारण, जिस लिए मैं पूछ रहा हूँ, यह है कि निधियों की लागत में तिमाही से तिमाही के आधार पर लगभग 20 बीपीएस की कमी हुई है। इसलिए सिर्फ वह आँकड़ा ज्ञात करने की कोशिश के लिए क्या किया जा ...?
- आर. नागराजन पहला, इस तिमाही में बॉण्ड यील्ड बहुत नीचे आ गए हैं। दूसरा हमने कुछ कमर्शियल पेपर्स भी उगाहे हैं तथा तीसरा अगस्त 2012 में उगाहे गए ईसीबी में हमको पूरा फायदा हुआ है। वास्तव में अगस्त 2012 में हमने ईसीबी के लिए पूरी अपफ्रंट फीस का भुगतान कर दिया था तथा वित्तीय वर्ष 2013 की तीसरी तिमाही की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013 की दूसरी तिमाही में रेट लगभग 225 बीपीएस था। ये तीन कारण हैं, जिनसे कॉस्ट नीचे आई है।
- राहुल जैन दूसरी बात, जल्दी से यह समझना चाहेंगे कि कोल प्राइसिंग पूलिंग पर क्या हो रहा है, ऐसा कुछ जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए.....?
- आर. नागराजन मैं सोचता हूँ कि बजट से पहले पावर क्षेत्र तथा गेस क्षेत्र में भी कुछ होगा। सीसीआई ने मंत्रालय को पहले ही 14 ब्लाकों में "नो-गो" को सुलझाने के निर्देश दे दिए हैं। वास्तव में समाचार पत्रों में बताया गया है कि 14 ब्लाकों में से 07 ब्लाकों को "नो-गो" से 'नो आब्जेक्शन' में अपग्रेड किया जा रहा है।

राहुल जैन सिर्फ एक अंतिम बात, आपने लगभग रुपए 4,500 करोड़..... के आपके रिस्ट्रक्चरिंग पोर्टफोलियो की चर्चा की है?

आर. नागराजन रुपए 4,984 करोड़।

राहुल जैन ओके, क्या इसमें नान-परफार्मिंग ऋण, जिन्हें रिस्ट्रक्चर किया गया है, वह भी शामिल है अथवा यह?

आर. नागराजन जी हाँ। इसमें नान-परफार्मिंग ऋण जैसे आरएस इण्डिया रुपए 224 करोड़ तथा महेश्वर रुपए 700 करोड़ भी शामिल हैं।

राहुल जैन क्या इस रुपए 4,984 करोड़ में नान-परफार्मिंग ऋण भी शामिल हैं?

आर. नागराजन जी हाँ।

मर्यादक बहुत-बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न हम इक्वीरस सिक्यूरिटीज़ के देवाँग मोदी से लेंगे। कृपया आप अपना प्रश्न पूछें।

देवाँग मोदी यह सिर्फ एक अनुवर्ती प्रश्न है। पहला, जैसा कि आपने बताया है कि आपको वित्तीय वर्ष 2014 में रुपए 11,306 करोड़ की सम्पत्तियाँ आने का अनुमान है?

आर. नागराजन आप उन सम्पत्तियों की चर्चा कर रहे हैं, जो आनेवाले वर्ष में कमीशनिंग होंगी।

देवाँग मोदी इसमें आपने बताया है कि आपके पास रुपए 33,000 करोड़ पहले ही ग्राउण्ड में हैं?

आर. नागराजन कमीशंड आउटस्टेण्डिंग रुपए 33,787 करोड़ है।

देवाँग मोदी हमारे पास कुल एक्सपोजर रुपए 1,21,181 करोड़ का है?

आर. नागराजन कमीशंड केटेगरी में रुपए 33,787 करोड़ तथा कमीशंड बकाया का ब्यौरा इस प्रकार है:- वित्तीय वर्ष 2012-13 में रुपए 23,885 करोड़, वित्तीय वर्ष 2013-14 में रुपए 35,586 करोड़, वित्तीय वर्ष 2014-15 में रुपए 11,306 करोड़, वित्तीय वर्ष 2015-16 में रुपए 569 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2016-17 में 2417 करोड़।

देवाँग मोदी 2013 के लिए यह आँकड़ा रुपए 23,885 करोड़ है, तो जैसा आपने बताया है रुपए 33,787 करोड़ की उत्पादन सम्पत्ति में इसे शामिल किया जाना है।

आर. नटराजन यह इस पर निर्भर करेगा कि मार्च तक यह कमीशंड होंती है या नहीं।

देवाँग मोदी तो वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए इसका आँकड़ा कितना है?

आर. नटराजन वित्तीय वर्ष 2013-14 में रुपए 35,586 करोड़ है।

- देवांग मोदी इस पर सिर्फ एक प्रश्न और। बैंक द्वारा दिए गए किसी भी ऋण पर, उदाहरण के लिए मान लें, एसबीआई के ऋण पर प्राईसिंग एसबीआई पीएलआर तथा एक विशेष स्प्रेड है। तो ऐसे विशेष तरीके से हमारे ऋण की प्राईसिंग कैसे करेंगे?
- आर. नटराजन पीएफसी में कोई बेस रेट सिस्टम या पीएलआर नहीं है। फिर भी, स्टेट क्षेत्र कर्जदारों के मामले में हम 'ए प्लस', ए, बी, सी रेटिंग का अनुसरण करते हैं तथा प्राईवेटक्षेत्र के कर्जदारों के मामले में आईआर1, आईआर2, 3, 4, 5 व 6 का अनुसरण करते हैं। आईआर6 विनियोग/इनवेस्टमेंट ग्रेड नहीं है, इसलिए हम इस श्रेणी को ऋण नहीं देते हैं। कर्जदारों की रेटिंग के आधार पर, वह ए प्लस या ए या बी या सी है, हम लागू ब्याज की दर प्रभारित करते हैं। हमारे इस सिस्टम की विशिष्टता सिर्फ यह है कि भुगतान की तिथि को लागू ब्याज की दर ही प्रभारित ब्याज की दर होगी। मान लें, रुपए 200 करोड़ का एक ऋण है। जनवरी 2013 में लगभग 12 प्रतिशत का रेट है तथा हम रुपए 100 करोड़ का भुगतान 12 प्रतिशत पर करते हैं, 1 मार्च 2013 यदि रेट 10 प्रतिशत है, तो शेष रुपए 100 करोड़ के भुगतान के लिए हम 10 प्रतिशत का रेट प्रभारित करेंगे। और 12 प्रतिशत का पिछला रेट लागू नहीं होगा। फिर भी यदि यह राशि तीन वर्षीय रिसेट के क्लॉज़ में कवर होती है, तो वे क्रमशः 01 जनवरी 2016 तथा 01 मार्च 2016 को रिसेट की पात्रता रखेंगे अर्थात् रुपए 100 करोड़ को 01 जनवरी 2016 को तथा दूसरे रुपए 100 करोड़ को 01 मार्च 2016 को रिसेट की तिथियों पर लागू रेट से रिसेट किया जा सकेगा।
- देवांग मोदी यह 12 प्रतिशत या 10 प्रतिशत की दर, जो आप लागू करेंगे, जनरल इन्डेक्स पर निर्भर करेगी या यह सामान्य तौर पर पीएफसी द्वारा ले ली गई है। मैं यह इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि यह रेट लेने के लिए क्या बेंचमार्क हैं?
- आर. नटराजन यह हमारी उधारियों की लागत से जुड़ी है। मान लें आरबीआई 100 बीपीएस से रेट कट कर देती है तथा बॉण्ड से लाभ 50 बीपीएस गिर जाता है तो स्वाभाविक तौर पर मैं भी रेट 50 बीपीएस कम कर दूँगा।
- देवांग मोदी लेकिन इस प्रकार से यह तो एक एड हॉक समायोजन हुआ, क्या कोई विशेष पीएलआर अथवा आंतरिक तरीके से अपनाई जानेवाली अन्य कोई व्यवस्था नहीं है?
- आर. नागराजन पीएफसी में कोई बेस रेट सिस्टम या पीएलआर नहीं है। हमारे पास बॉरोइंग प्लस मार्जिन का सिस्टम है तथा उधार देने का रेट उधार लेनेवाले की रेटिंग पर निर्भर है, जैसे कि स्टेट क्षेत्र में ए प्लस के लिए न्यूनतम तथा बी के लिए उच्चतम है, प्राईवेट क्षेत्र में आईआर-1 के लिए न्यूनतम है, ये यदाकदा ही होता है।

मर्यादक बहुत-बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न हम आनंद राठी से आए कैटव शाह से लेंगे। कृपया आप अपना प्रश्न पूछें।

कैटव शाह मैं लेन्को के एक्सपोजर पर आपका दृष्टिकोण जानना चाहूँगा? यह कैसा चल रहा है?

आर. नागराजन लेन्को में हमें रुपए 3,162 करोड़ का एक्सपोजर मिला है। उडुपी के मामले में इसने रुपए 3.2/- किलोवाट प्रति घंटे का पीपीए हस्ताक्षरित किया है तथा उसके बाद रुपए 4.37/ किलोवाट प्रति घंटे के रिवीजन की माँग की है। सीईआरसी में इन्होंने केस जीत लिया है तथा कर्नाटक राज्य सरकार के पास लगभग रुपए 600-800 करोड़ के भुगतान हेतु याचिका फाईल की है। इसलिए वे अभी भी सोवैरियन रिस्क का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी राज्य की वितरण कम्पनी द्वारा देयताओं का भुगतान किया जाना बाकी है। आशा है एक बार जब वितरण कम्पनी की लिक्विडिटी पोजीशन सुधर जाएगी, तब एग्रीमेंट के अनुसार उनके द्वारा देयताओं का भुगतान कर दिया जाएगा।

कैटव शाह और सुज़लान, आज तक कितने दिनों का आवेरड्यू है?

आर. नागराजन 31 दिसम्बर 2012 को लगभग रुपए 85 करोड़ का बकाया है (मूलधन, ब्याज तथा ब्याज पर ब्याज का बकाया)। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह एनपीए न हों।

कैटव शाह यदि आपकी अनुमति हों तो एक आखरी प्रश्न। अगले वर्ष के लिए भुगतान और स्वीकृतियों के बारे में आपका दृष्टिकोण क्या है?

आर. नागराजन सबसे पहले हम मार्च 2013 में बहुत अच्छे परफार्मेंस पर एकाग्र हों। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बजाए इसके कि हम 2014 के बारे में बात करें।

कैटव शाह तब महोदय हमें चौथी तिमाही के बारे में अपना दृष्टिकोण बताएं?

आर. नागराजन दिसम्बर 2012 से डॉलर के विरुद्ध रुपए में बढ़ोत्तरी हुई है तथा डॉलर के विरुद्ध येन में गिरावट आई है। येन के एक्सपोजर में 91 के वर्तमान स्तर के विरुद्ध हमें 82 तथा 84 के स्तर पर बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला है। इसलिए विदेशी दायित्वों के पोर्टफोलियो में यदि हम कोई हेजिंग/कमी नहीं भी करते हैं, मार्केट टू मार्केट बेसिस पर हमें फायदा होगा। बेलेंस टेक्स फ्री बॉण्ड आवंटन से बढ़ने से भी हमें फायदा मिलेगा। पहले रेज़्ड टेक्स फ्री बॉण्ड के बारे में, आनेवाली तिमाही में पूरा फायदा मिलेगा। ईसीबी की रेज़िंग तथा एमटीएन. प्रोग्राम से भी फायदा मिलेगा। इसलिए इस तिमाही में हमने जो किया है, उसके जैसा ही परफार्मेंस होना चाहिए।

मर्यादक बहुत-बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न हम गोल्डमेन सेक्स के हिरेन दसानी से लेंगे। कृपया आप अपना प्रश्न पूछें।

हिरेन दासानी सिर्फ एक बात। यह रुपए 92 करोड़ का प्रावधान, जो आपने प्रस्तुतिकरण में बताया है, यदि आप इसे लाभ एवं हानि लाईन के आईटम के अनुसार देखें, तो इसे कहाँ दर्शाया जाएगा?

आर. नागराजन यह लाभ के विरुद्ध एक प्रभार होगा।

हिरेन दासानी मैं यह समझता हूँ लेकिन यदि आप आपके स्टेट्यूटरी डिस्क्लोज़र टू द एक्सचेंज को देखें, तो यह कहीं भी अलग से नहीं दर्शाया गया है?

आर. नागराजन यह ब्याज तथा अन्य प्रभारों का भाग है।

हिरेन दासानी तो वित्तीय व्यय, सही है?

आर. नागराजन जी हाँ।

हिरेन दासानी और अगला प्रश्न यह है कि यदि हम इन 05 एसईबी की ओर देखें, जहाँ आपने ट्रांजीशनल फाइनेंस उपलब्ध कराया है: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु, सभी को मिलाकर, इसे ओवरऑल सिस्टम्स के एसईबी नुकसानों के कितने प्रतिशत तक की गणना की जाएगी ?

आर. नागराजन 05 राज्यों का नुकसान कुल मिलाकर ओवरऑल सिस्टम के नुकसानों का 50 से 60 प्रतिशत के लगभग होगा। इसलिए भारत सरकार के इन राज्यों पर ध्यान दिया जा रहा है।

हिरेन दासानी क्या सभी ने या तो द्विपक्षीय आधार पर या सेन्ट्रल आधार पर एफआरपी को कार्यान्वित किया है?

आर. नागराजन इन्होंने सेन्ट्रल बेसिस पर कार्यान्वित किया है। तमिलनाडु ने राज्य मंत्रिमंडल तथा विनियामक से सैद्धांतिक अनुमोदन ले लिया है तथा केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर दिया है तथा इस योजना के अनुसार समिति का गठन भी कर दिया है। समाचार पत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश ने भी राज्य मंत्रिमंडल से अनुमोदन ले लिया है तथा इस ऑफर के लिए केन्द्र सरकार के पास जाने से पूर्व उन्हें विनियामक के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। हरियाणा और राजस्थान भी राज्य मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के सम्पर्क में है। इस प्रकार से कम से कम 3 राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा एफआरपी के अनुपालन हेतु इच्छुक हैं।

हिरेन दासानी और पंजाब द्विपक्षीय करनेवाला है?

आर. नागराजन पंजाब एफआरपी योजना के लिए नहीं जा रहा है।

हिरेन दासानी क्या ऐसा इसलिए, क्योंकि एफआरपी के बिना भी वे लाभ कमाने की ओर अग्रसर है?

आर. नागराजन वे लाभ कमाने की ओर अग्रसर हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही लगभग 59 प्रतिशत बढ़ोत्तरी का भारी प्रशुल्क पुनरीक्षण नवम्बर 2012 में फाईल किया है और उन्हें लगता है कि एक साल में 2014 तक वे केश सरप्लस बन जाएंगे।

हिरेन दासानी यदि वे एफआरपी को कार्यान्वित नहीं करते हैं तो किस योजना के तहत हम भुगतान करेंगे?

आर. नागराजन राज्य में प्रशुल्क बढ़ाने के साथ, सरकार भी उनके मदद करेगी। एफआरपी पर 05 अक्टूबर 2012 को जारी परिपत्र (परिशिष्ट 1) में दिए गए आँकड़ों के आधार यह देखा जा सकता है कि हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की तुलना में पंजाब के पास अल्पावधि ऋण की राशि कम है। मध्य प्रदेश के पास भी अल्पावधि ऋण का बकाया सिर्फ रूपए 585 करोड़ है। एफआरपी योजना का लाभ सिर्फ उनको है जिनके पास पर्याप्त अल्पावधि ऋण है, क्योंकि सिर्फ अल्पावधि ऋण को ही दीर्घावधि ऋण में बदला जाएगा।

हिरेन दासानी इन 04 राज्यों में अल्पावधि ऋण की राशि ज्यादा है?

आर. नागराजन जी हाँ, इनके पास अल्पावधि ऋण बहुत ज्यादा है।

हिरेन दासानी और पंजाब के पास यह नहीं है?

आर. नागराजन पंजाब के पास हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु व उत्तर प्रदेश की तुलना में अल्पावधि ऋण की राशि कम है।

हिरेन दासानी लेकिन पंजाब ने भी बैंकों के साथ कुछ द्विपक्षीय रिस्ट्रक्चरिंग की है, सही है?

आर. नागराजन जी हाँ। द्विपक्षीय तौर पर उन्होंने कुछ बैंकों के साथ रिस्ट्रक्चरिंग की है, लेकिन वे विद्युत मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही केन्द्रीय एफआरपी के लिए नहीं आए हैं।

आर. नागराजन धन्यवाद। अगला प्रश्न हम स्पार्क कैपिटल के ज्योति कुमार से लेंगे। कृपया आप अपना प्रश्न पूछें।

ज्योति कुमार सिर्फ एक प्रश्न। हम क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर जनरेशन सेगमेंट की स्वीकृतियों में बहुत उछाल देख रहे हैं, पिछली तिमाही में यह कुछ रूपए 6,000 करोड़ थी व चालू तिमाही में यह लगभग रूपए 12,000 करोड़ है?

आर. नागराजन यह तमिलनाडु जनरेशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन को दी गई रूपए 8,151 करोड़ की बड़ी स्वीकृति के कारण है।

ज्योति कुमार जी हाँ महोदय। मैं यह देख रहा हूँ तथा ये पावर परियोजनाओं की तरफ है?

आर. नागराजन यह एन्नोर सेज में कोयले पर आधारित सुपर क्रिटीकल टीपीपी (2×800 एमडब्ल्यू) के लिए स्वीकृत की गई है।

ज्योति कुमार नहीं, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या ये इसका साइन है कि लोग अब पावर जनरेशन सेगमेंट में अपनी पूंजीलगाने के इच्छुक हैं?

आर. नागराजन राज्य सरकार के लिए पूंजीका कोई इश्यू नहीं है, राज्य सरकार के लिए इन परियोजनाओं में इक्विटी लाने में कोई मुश्किल नहीं है।

ज्योति कुमार लेकिन हकीकत में प्राइवेट से वास्तव में कोई सुधार नहीं हुआ है.....

आर. नागराजन हमें अभी भी प्राइवेट क्षेत्र से कुछ प्रस्ताव आ रहे हैं, क्योंकि उनकी एकजोड़र लिमिट के कारण अधिकतर बैंक उन्हें फण्डिंग नहीं कर रहे हैं। आप हमारी स्वीकृतियों के आँकड़ों से देख सकते हैं कि रुपए 45,150 करोड़ के भारत सरकार के साथ सहमति के एमओयू टारगेट के विरुद्ध हमने पहले ही लगभग रुपए 58,682 करोड़ का लक्ष्य पा लिया है। यदि आप ट्रांजीशनल फण्डिंग की राशि लगभग रुपए 16,630 का आँकड़ा निकाल भी दें, तो भी हमने वित्तीय वर्ष 2013 के 09 महीनों में रुपए 42,052 करोड़ स्वीकृत किए हैं, जो कि पूरे वर्ष के लक्ष्य से सिर्फ रुपए 3,098 करोड़ कम है।

ज्योति कुमार यदि मैं सिर्फ संकेत दे सकूँ, यदि मैं सिर्फ भुगतान के आँकड़े, ट्रांजीशनल फाइनेंस के लिए समायोजन को देखूँ, वास्तव में हमारे भुगतान 09 माह के आधार पर अधिकांशतः समान रहे हैं। इसलिए मैं यदि आगे का अनुमान देखना चाहूँ, तो इसका मतलब होगा कि हम वित्तीय वर्ष 2014 में ऋण में बढ़ोत्तरी की दिशा में परेशानियों का सामना करने जा रहे हैं?

आर. नागराजन पहले हम 31 मार्च 2013 के बारे में बात कर लें। जनवरी 2012 की तुलना में समग्र रूप से परिस्थितियों में बहुत सुधार हुआ है। एफएसए में बहुत सारी परेशानियाँ थी जिसमें कुछ संकल्प लिए गए तथा अब तक कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा 42 एफएसए को पहले ही हस्ताक्षरित किया जा चुका है। सीसीआई ने कल एक बैठक की है जिसमें गैस व ऑयल क्षेत्र पर चर्चा की है तथा अब आगे पावर क्षेत्र पर चर्चा की जाएगी। एफएसए तथा पर्यावरण अनुमति पर चर्चा की जाएगी। स्थितियाँ निराशाजनक नहीं हैं, तथा मैं सोचता हूँ कि जनवरी 2012 की तुलना में 2013 में स्थिति निश्चित तौर पर अच्छी रहेगी, इसलिए हमें 2013-14 की वृद्धि के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए।

ज्योति कुमार और अंत में आँकड़ों के बारे में, मैं अगले साल रिप्राइस्ड की जानेवाली सम्पत्तियों की राशि तथा रिप्राइस्ड किए जाने वाले दायित्वों का विवरण नहीं सुन पाया हूँ?

आर. नागराजन अगले वर्ष रुपए 48,735 करोड़ की सम्पत्तियों तथा रुपए 39,788 करोड़ के दायित्वों की रिप्राइसिंग रिपीट रिसेट को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

मर्यादक धन्यवाद। अगला प्रश्न हम एशियन मार्केट सिक्कूरिटीज के कमलेश कोटक से लेंगे। कृपया आप अपना प्रश्न पूछें।

कमलेश कोटक क्या आप थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स अथवा थर्मल पावर परियोजनाओं में महत्वपूर्ण अंश स्वामित्व (स्ट्रेटेजिक स्टेक्स) लेने के बारे में कम्पनी की रणनीति के बारे में प्रकाश डालेंगे?

आर. नागराजन मैं सोचता हूँ कि आप समाचार पत्रों की खबर, कि पीएफसी नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन में रुपए 200 करोड़ का अंश स्वामित्व ले रही है, के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पास इक्विटी पॉलिसी है, जिसे निदेशक मंडल द्वारा लगभग छः से सात महीने पहले अनुमोदित किया गया है तथा हम उसी पर आधारित प्रस्ताव ले रहे हैं। फिर भी, हमने नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन का कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया है।

मर्यादक बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों एवं सज्जनों, यह आखरी प्रश्न था। जे0एम0 फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूटशनल सिक््योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से इस सम्मेलन कॉल को समाप्त किया जाता है। हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद और अब आप अपनी लाईनें काट सकते हैं। श्री नागराजन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।